पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) बाघ परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में इस समय पांच राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को शामिल करने के प्रस्ताव हैं।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान निधियों की कमी के कारण परियोजना पर अगली योजना अवधि के दौरान विचार किया जा सकता है।

Agreements with Malaysian Group for National Super Highways

2260. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether tenders floated for National Super Highways about feasibility has been ignored for NSH-2 before entering into agreements with a Malaysian group;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether agreement for NSH-2 is controversial as reported in Indian Express dated 2nd August, 1995; and

(d) if so, the steps taken to rectify the undue advantages proposed in the agreement?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No agreement has been entered into with any private Malaysian group for construction of any Super National Highway.

(b) to (d) In view of (a) above, (b), (c) & (d) do not arise.

भारतीय व्यापारियों को अमरीकी वीजा प्राप्त करने में समस्या पेश आना

2261. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई वीजा प्रणाली के कारण भारतीय व्यापारियों को अमरीकी वीजा प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार से संपर्क कायम किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) 13 जनवरी, 1995 से लागू नए अमरीकी विनियमों के कारण भारतीय व्यवसायियों के लिए समय से वीजा प्राप्त करना कठिन हो गया है। इससे उन भारतीय व्यवसायियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो सेवा प्रदान करने के लिए, विशेषकर सोफ्टवेयर के क्षेत्र में अमरीका जाना चाहते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने भारत और अमरीका दोनों में ही विभिन्न स्तरों पर अमरीका की सरकार को भारत की चिन्ता से अवगत करा दिया है। इस बात पर बल दिया गया है कि इन नए नियमों से उन परियोजनाओं में विलम्ब होगा जो संविदा तथा भागीदारी के आधार पर अमरीका उद्योग के लिए भारतीय संगठनों द्वारा निष्पादित की जा रही है।

अमरीका की सरकार इस संबंध में भारत की हित-चिन्ता से अवगत है और उसे समझती है। इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में भी चर्चा की जा रही है क्योंकि अमरीकी विनियम केवल भारत के लिए ही नहीं हैं बल्कि सभी कुशल विदेशी व्यवसायियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

सरकार इस संबंध में गतिविधियों को ध्यानपूर्वक मानीटर कर रही है तथा इस संबंध में भारत के हितों की रक्षा के प्रति सचेत है।

Delhi-Bomaby Expressway

2262. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Delhi-Bombay Expressway-con-

sultants to be appointed" as reported in the Statesman dated 19th June, 1995;

(b) if so, whether the consultants for the Delhi-Bombay Expressways have since been appointed;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of other highways to be declared as expressways in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) It is too early to indicate the details of Highways to be declared as Expressways.

Role of Indian missions abroad

2263. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are examining the question of coordination with the Ferderation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) and the Confederation of Indian Industry (CII) for opening their overseas offices with a view to get greater response for India's economic liberalisation abroad; and

(b) if so, whether commercial and economic wings of the Indian missions abroad are being suitably strengthened as to attract much needed foreign investment and to give necessary thrust to the country's trade and economic activities and if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Government work closely with the apex Chambers of Commerce and Industry including Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Confederation of Indian Industry (CII), in projecting India's economic profile and liberalisation policies abroad and in promoting stronger trade and economic relations with countries around the world. In this regard, Government have encouraged and supported requests from apex chambers to establish their offices abroad.

(b) From time to time, Government review the capabilities of the economic and commercial wings of its Missions and Posts abroad. Steps are taken to ensure that necessary back-up support including adequate staff strength, equipment and publicity and promotional material is available in order to enable Missions to promote our commercial and economic interests effectively.

दिल्ली में लावारिस लाशों के मामले

2264. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 और वर्ष 1995 में 31 जुलाई, 1995 तक वर्ष-वार दिल्ली पुलिस ने कितनी लावारिस लाशें बरामद कीं;

(ख) क्या यह सही है कि दिल्ली में कुछ हत्या की घटनाओं के मामले में शव पड़ोसी राज्यों में पाये गये, यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हुए हैं;

(ग) उपर्युक्त लाशों में से कितनों की शिनाख्त हुई है और कितनों की शिनाख्त नहीं हो पायी; और

(घ) दिल्ली पुलिस ने ऐसे कितने मामले दर्ज किये हैं और भारतीय दंड संहिता की किन-किन धाराओं के अन्तर्गत इन मामलों को दर्ज किया गया है और इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सूचना निम्न प्रकार है:—